Expansion of Postal Service in Hilly and Rural Areas

2207. SHRI SATISH CHANDRA SITARAM PRADHAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have undertaken any survey to modernise the postal services through the induction of new technology in the country; and

(b) if so, the steps taken/proposed to be taken by Government for expansion of postal services in inaccessible, hilly parts and rural areas of the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KABINDRA PURKAYASTHA): (a) and (b) Yes, Sir. The Department of Posts during the last few years has been inducting computer and communication technologies into the Post. Computer based multipurpose counter machines have been installed where the customer can carry out all transactions at a single window. These machines have been installed in remote areas like Rekong PO, Badi (HP), Kathua (J&K), Imphal, Kohima, Aizwal, Itanagar etc. 75 VSATs (Very Small Aperture Terminals) have been installed alongwith 610 Extended Satellite Money Order Stations for money transfer from major urban centres to the hinterland including inaccessible, hilly parts and other rural areas such as Rynjah (Shillong), Nogpah (Shimla), Joginder Nagar (HP), Kawarati (Lakshdweep) etc.

दूरभाषों की "मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो" प्रणाली

2208. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एम.ए.आर.आर. प्रणालीयुक्त दूरभाष केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है,

(ख) इस प्रणाली के ठीक से कार्य न कर पाने के क्या कारण है,

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में किस वैकल्पिक प्रणाली को अपनाया जाएगा, और

(घ) इस प्रणाली वाले केन्द्रों को बदलने के लिए वर्ष 1995-96 से 1998-99 तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) देश में एमएआरआर प्रणालियों से सज्जित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं। (नीचे देखिए)

(ख) निम्नलिखित कारणों से एमएआरआर प्रणालियों का निष्पादन आशा से कम रहा है :-

(i) एमएआरआर प्रौद्योगिकी का कम विश्वसनीय होना।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में बार-बार बिजली जाना तथा काफी देर बिजली न जाना।

(iii) उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ब्रिकी के बाद अपेक्षित सेवाएं न देना।

(iv) ऐसे स्थानों पर पहुंचने में कठिनाई होना/ उनका दुर्गम् होना, जहां उपस्कर लगाए गएं हैं।

(v) बीपीटी धारकों द्वारा पर्याप्त ध्यान न दिया जाना तथा ग्रामवासियों द्वारा बैटरियों का दुरूपयोग किया जाना।

(ग) एक्सचेंज से 3-5 कि.मी. की कम दूरी के लिए लैण्ड लाइनों के इस्तेमाल के अतिरिक्त सरकार, 1999-2000 से शामिल किए जाने वाली निम्नलिखित वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों पर विचार कर रहीं हैं :

(i) स्थानीय लूप में बेतार/डब्ल्यू एस एल)

(ii) सी-डॉट टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस/प्वाइंट-टू-मल्टी प्वाइंट प्रणालियों।

(iii) दूरस्थ तथा दुर्गम गांवों में उपग्रह प्रौद्योगिकी।

(घ) जहां पहले एमएआरआर आधारित वीपीटी पर सौर-पैनल नहीं लगाएं गए हैं उन पर सौर पैनल लगाना

- एसएसए तथा सर्किल स्तर पर दैनिक रूप से वीपीटी दोषों पर निगरानी रखना।

-विनिर्माताओं के साथ वार्षिक अनुरक्षण ठेके किए जा रहें हैं।

-दोषयुक्त वीपीटी को ठीक करने के लिए दूरसंचार विभाग के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

- दूरसंचार सर्किलों के महत्वपूर्ण स्थानों पर मरम्मत केन्द्र खोले जा रहें हैं।

जहां व्यवहार्य हो कुछेक एमएआरआर प्रणालियों के स्थान पर लैंड लाइनों की व्यवस्था करना।

पुरानी तथा बेकार एमएआरआर प्रणालियों को चरणबद्ध तरीके से बदला जा रहा है।

- अतिरिक्त पूर्जों की प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है।

- उत्तरोत्तर रूप से विश्वसनीय संचारण माध्यम प्रदान किया जा रहा है।

- गुमशुदा/ क्षतिग्रस्त सौर-पैनलों को बदला जा रहा है।

विवरण

देश में एम ए आर आर प्रणाली से सज्जित एक्सचेंजों का राज्यवार बयौरा

क्रं. सं.	सर्किल/राज्य	एमएआरआर प्रणाली से सज्जित एक्सचेंजों की संख्या	एमएआरआर पर ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार	6	110
2.	आंध्र प्रदेश	676	12311
3.	असम	250	7225
4.	बिहार	390	10971
5.	गुजरात	418	7413
6.	हरियाणा	129	3634
7.	हिमाचल प्रदेश	161	2433
8.	जम्मू एंव कश्मीर	88	2076
9.	कर्नाटक	633	13098
10	केरल	60	32
11.	मध्य प्रदेश	1354	21082
12.	महाराष्ट्र	1220	17385
13.	गोवा	8	190
14.	अरूणाचल प्रदेश	37	416
15.	मणिपुर	28	548
16.	मेघालय	45	962
17.	मिजोरम	27	480
18.	नागालैंड	23	455
19.	त्रिपुरा	20	355
20.	उड़ीसा	310	10702
21.	पंजाब	202	6126
22.	राजस्थान	682	17060

क्रं. सं.	सर्किल/राज्य	एमएआरआर प्रणाली से सज्जित एक्सचेंजों की संख्या	एमएआरआर पर ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या
23.	तमिलनाडु	357	7171
24.	उत्तर प्रदेश पूर्व	1387	23931
25.	उत्तर प्रदेश पश्चिम	408	10693
26.	पश्चिम बंगाल	291	8716
27.	सिक्किम	5	70
28.	कलकत्ता	6	56
	योग	9221	185701

नई संचार नीति का निर्माण

2209. **श्री कपिल सिब्बल** :

श्री बलवन्त सिंह रामूवायिलया:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा नई दूरसंचार नीति तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई है,

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब गठित की गई और उक्त समिति के सदस्यों के नाम क्या-क्या है,

(ग) क्या समिति द्वारा कार्य पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है, और

(घ) यदि हां, तो वह समय-सीमा क्या है और सरकार कब तक नई दुरभाष नीति की घोषणा करने का विचार रखती है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) प्रस्तावित नई दूरसंचार नीति के लिए सिफारिशें देने हेतु एक दूरसंचार समूह गठित किया गया है।

(ख) इस समूह का गठन 2011.98 को किया गया था। सदस्यों की वर्तमान सूची विवरण में दी गई है। (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) इस समूह संबंधी आदेशों के अनुसार इस समूह को प्रधान मंत्री को अपनी सिफारिशें यथाशीघ्र देनी है।

विवरण

दूरसंचार समूह का गठन :

अध्यक्ष-

1. श्री जसवंत सिंह,
विदेश मंत्री एंव इलेक्ट्रानिकी मंत्री

सदस्य

2. वित्त मंत्री
3. रक्षा मंत्री
4. संचार मंत्री
5. सूचना और प्रसारा मंत्री
6. श्री के.सी. पन्त
उपाध्यक्ष, योजना आयोग
7. सदस्य (संचार) योजना आयोग
8.प्रधान मंत्री के सचिव

सदस्य सचिव

9. वित्त सचिव
10. विधि सचिव
11. सचिव सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय,
12. सचिव दूरसंचार
13. सदस्य (सेवाएं) दूरसचांर आयोग
14. सदस्य (उत्पादन) दूरसंचार आयोग
15. डा. एन शेषगिरी
महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र